

# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

## जिला बड़वानी में अनुसूचित जनजाति समाज में लैंगिक असमानता के परिवर्तन: एक अनुभवजन्य समाजशास्त्रीय अध्ययन

**Kundan Gathe**

Research Scholar, Department of Sociology , Malwanchal University, Indore

**Dr. Sonali Pandit**

Supervisor, Department of Sociology , Malwanchal University, Indore

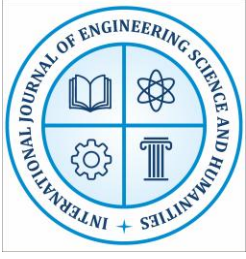
### सारांश

यह शोध "जिला बड़वानी जिला में अनुसूचित जनजाति समाज में लैंगिक असमानता के परिवर्तन" का एक अनुभवजन्य समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन आया है। प्राथमिक आंकड़ों (सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार) के आधार पर यह पाया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं निर्णय-निर्माण के क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है, किंतु असमानता अब भी विभिन्न रूपों में विद्यमान है। पारंपरिक मान्यताओं, संसाधनों की कमी एवं जागरूकता के अभाव के कारण परिवर्तन की गति धीमी है, जबकि सरकारी योजनाओं, शिक्षा एवं स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव से सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। यह अध्ययन दर्शाता है कि लैंगिक असमानता एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रभाव परिलक्षित होता है।

**मुख्य शब्द:** लैंगिक असमानता, अनुसूचित जनजाति, अनुभवजन्य अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण

### प्रस्तावना

भारतीय समाज की संरचना विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसमें अनुसूचित जनजाति समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि जनजातीय समुदायों को परंपरागत रूप से अपेक्षाकृत समानतावादी माना जाता रहा है, तथापि वास्तविकता में इन समाजों में भी लैंगिक असमानता विभिन्न रूपों में विद्यमान है, जो समय के साथ बदलती सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो रही है। विशेष रूप से बड़वानी जिला, जो मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में से एक है, वहाँ के सामाजिक जीवन, आजीविका के साधन, शिक्षा की स्थिति तथा सांस्कृतिक परंपराएँ महिलाओं की भूमिका और उनकी स्थिति को प्रभावित करती हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय एवं निर्णय-निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक असमानता के विभिन्न आयाम विद्यमान हैं। पारंपरिक



# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

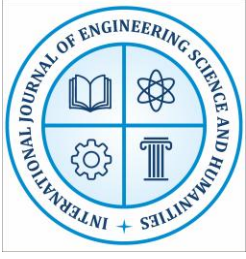
मान्यताएँ, सीमित संसाधन, अशिक्षा तथा आर्थिक निर्भरता महिलाओं की प्रगति में प्रमुख बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। साथ ही, आधुनिकता, शहरीकरण, शिक्षा के प्रसार एवं सरकारी योजनाओं के प्रभाव से इन असमानताओं में परिवर्तन की प्रक्रियाएँ भी देखी जा रही हैं, जिनके कारण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी में कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य बड़वानी जिले के अनुसूचित जनजाति समाज में लैंगिक असमानता के स्वरूप एवं उसके परिवर्तनों का अनुभवजन्य विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत प्राथमिक डेटा (survey, interview) के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक कारक महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं तथा समय के साथ उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं। यह अध्ययन न केवल क्षेत्रीय स्तर पर लैंगिक असमानता की वास्तविक स्थिति को उजागर करेगा, बल्कि नीति-निर्माण, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों तथा सामाजिक हस्तक्षेप के लिए भी उपयोगी दिशा प्रदान करेगा, जिससे समावेशी एवं संतुलित विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

## अध्ययन का औचित्य

यह अध्ययन इसलिए औचित्यपूर्ण है क्योंकि अनुसूचित जनजाति समाज, विशेषकर बड़वानी जिला में लैंगिक असमानता की वास्तविक स्थिति एवं उसके परिवर्तनों पर क्षेत्रीय स्तर पर अनुभवजन्य शोध अपेक्षाकृत सीमित है। प्रायः जनजातीय समाज को समानतावादी माना जाता है, परंतु शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं निर्णय-निर्माण जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में इस विषय का अध्ययन न केवल सामाजिक यथार्थ को उजागर करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि सरकारी योजनाएँ, शिक्षा एवं जागरूकता किस सीमा तक प्रभावी रही हैं। यह शोध नीति-निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रदान करेगा, जिससे जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अधिक प्रभावी एवं क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप विकसित किए जा सकें और समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

## अध्ययन की पृष्ठभूमि

भारत के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाएँ विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों से निर्मित हुई हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव लैंगिक संबंधों पर पड़ता है। बड़वानी जिला जैसे क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय पारंपरिक जीवन-शैली, सीमित संसाधनों और प्रकृति-आधारित आजीविका पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण महिलाओं की भूमिका बहुआयामी होने के बावजूद उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बनी रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं निर्णय-निर्माण में लैंगिक असमानता के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में शिक्षा के प्रसार, सरकारी योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा सामाजिक जागरूकता के प्रभाव से इन असमानताओं में कुछ परिवर्तन भी दृष्टिगत हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में यह अध्ययन जनजातीय समाज में लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं उसके परिवर्तनों को समझने का प्रयास करता है।



# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

## अध्ययन क्षेत्र का परिचय

### 1. बड़वानी जिला का भौगोलिक परिचय

बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित एक प्रमुख जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जो नर्मदा नदी के किनारे एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के समीप अवस्थित है। जिले का भौगोलिक स्वरूप मुख्यतः पहाड़ी, वनाच्छादित एवं आंशिक रूप से मैदानी है, जिससे यहाँ के निवासियों की आजीविका और जीवन-शैली पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जलवायु अर्ध-शुष्क से उप-उष्णकटिबंधीय है, जहाँ वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण परिवहन, संचार एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता कई क्षेत्रों में सीमित रहती है, जिससे विकास की गति प्रभावित होती है।

### 2. जनजातीय जनसंख्या की संरचना

बड़वानी जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का महत्वपूर्ण अनुपात है, जिसमें भील, भिलाला एवं अन्य जनजातीय समुदाय प्रमुख हैं। ये समुदाय अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भाषा, परंपराओं एवं सामाजिक संरचना के लिए जाने जाते हैं। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करता है, जहाँ सामुदायिक जीवन एवं पारंपरिक संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जनसंख्या संरचना में युवा वर्ग का प्रतिशत अधिक है, जो विकास एवं परिवर्तन की संभावनाओं को दर्शाता है, हालांकि सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

### 3. सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

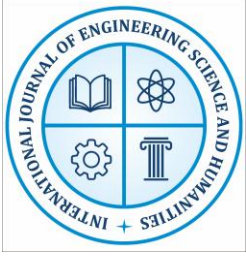
सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से बड़वानी जिले के जनजातीय समुदाय अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन एवं वनोपज पर आधारित है, जो अधिकतर निर्वाह स्तर (subsistence level) की होती है। गरीबी, संसाधनों की कमी एवं सीमित आय के अवरसर आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। सामाजिक संरचना में पारंपरिक मान्यताएँ एवं रीति-रिवाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका प्रभाव लैंगिक संबंधों एवं महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ता है।

### 4. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की स्थिति

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में बड़वानी जिले की स्थिति अभी भी चुनौतिपूर्ण है। साक्षरता दर विशेषकर महिलाओं में कम है, जिसका कारण विद्यालयों की दूरी, आर्थिक बाधाएँ एवं सामाजिक मान्यताएँ हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी सीमित है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ अधिक देखी जाती हैं। रोजगार के अवरसर मुख्यतः कृषि एवं असंगठित क्षेत्र तक सीमित हैं, जहाँ महिलाओं की भागीदारी तो अधिक है, परंतु उन्हें उचित पारिश्रमिक एवं सुरक्षा नहीं मिलती। इस प्रकार, यह क्षेत्र लैंगिक असमानता के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भ प्रदान करता है।

### साहित्य समीक्षा

आदिवासी महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर उपलब्ध साहित्य यह स्पष्ट करता है कि यह विषय बहुआयामी, जटिल तथा संरचनात्मक कारकों से प्रभावित है। गुप्ता, अंजलि (2018) के अध्ययन में



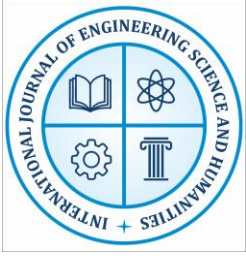
# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

आदिवासी महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों एवं नीतिगत उपायों के बावजूद जमीनी स्तर पर अधिकारों का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसी प्रकार शेख, राशिद (2018) ने आदिवासी महिलाओं पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक दबावों का विश्लेषण करते हुए यह बताया कि परंपरागत मान्यताएँ, रीति-रिवाज एवं लैंगिक भूमिकाएँ महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसरों को सीमित करती हैं। इन दोनों अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए केवल कानूनी ढांचे का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों का भी गहन विश्लेषण आवश्यक है। यह साहित्य इस तथ्य को पुष्ट करता है कि लैंगिक असमानता केवल संसाधनों की कमी का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं में अंतर्निहित असमानताओं का प्रतिफल है।

विकास कार्यक्रमों एवं नीतियों की प्रभावशीलता पर केंद्रित अध्ययनों ने आदिवासी महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयासों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। सिंह, नरेश कुमार (2018) ने विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अध्ययन करते हुए पाया कि यद्यपि विभिन्न सरकारी योजनाएँ महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू की गई हैं, परंतु उनके लाभ का वितरण समान रूप से नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक बाधाएँ, जागरूकता की कमी तथा स्थानीय स्तर पर संसाधनों का अभाव इन योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित करता है। इसी दिशा में सिंह, रश्मि (2019) ने विकास नीतियों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि नीतियों का निर्माण तो व्यापक दृष्टिकोण से किया जाता है, किंतु उनके क्रियान्वयन में क्षेत्रीय असमानताएँ और सामाजिक अवरोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि विकास नीतियों की सफलता केवल उनके निर्माण पर नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं स्थानीय सहभागिता पर निर्भर करती है। यह साहित्य इस बात की ओर संकेत करता है कि आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों को अधिक समावेशी एवं क्षेत्र-विशिष्ट बनाने की आवश्यकता है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के संदर्भ में आदिवासी महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने वाले अध्ययनों में पाटिल, विनीता (2019) एवं शर्मा, रवि कुमार (2019) के कार्य महत्वपूर्ण हैं। पाटिल (2019) ने आदिवासी महिलाओं की सामाजिक स्थिति और अधिकारों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह पाया कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक भागीदारी के क्षेत्रों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं शर्मा (2019) ने यह प्रतिपादित किया कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक—जैसे पारंपरिक मान्यताएँ, लैंगिक भूमिकाएँ एवं सामुदायिक संरचनाएँ—महिलाओं की प्रगति को प्रभावित करते हैं। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी महिलाओं की स्थिति केवल आर्थिक कारकों से नहीं, बल्कि गहराई से सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त, इन कारकों का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर भिन्न-भिन्न रूप में देखने को मिलता है, जिससे लैंगिक असमानता की प्रकृति और अधिक जटिल हो जाती है।



# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

आधुनिक संदर्भ में सामाजिक असमानताओं एवं लैंगिक मुद्दों पर केंद्रित अध्ययनों ने इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। कुमार, अजय (2019) ने आदिवासी महिलाओं पर सामाजिक असमानताओं के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि गरीबी, शिक्षा की कमी एवं संसाधनों तक सीमित पहुँच महिलाओं की स्थिति को कमजोर बनाती है। चौरसिया, शालिनी (2019) ने आदिवासी समाज में लैंगिक असमानता की समस्याओं एवं संभावित समाधानों पर प्रकाश डालते हुए यह सुझाव दिया कि शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक सशक्तिकरण एवं नीतिगत सुधारों के माध्यम से इस असमानता को कम किया जा सकता है। समग्र रूप से, उपलब्ध साहित्य यह इंगित करता है कि आदिवासी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुआयामी एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत सभी स्तरों पर हस्तक्षेप शामिल हो। साथ ही, यह भी स्पष्ट होता है कि यद्यपि विभिन्न प्रयासों के माध्यम से कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, फिर भी लैंगिक असमानता की समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है और इस दिशा में निरंतर अनुसंधान एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता बनी हुई है।

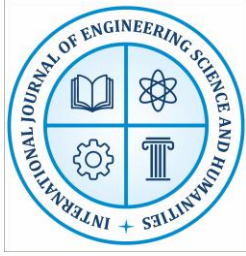
## सैद्धांतिक एवं वैचारिक रूपरेखा

### 1. लैंगिक असमानता की संकल्पना

लैंगिक असमानता से आशय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच अवसरों, संसाधनों, अधिकारों एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के असमान वितरण से है, जो जैविक भिन्नताओं के बजाय सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होती है। अनुसूचित जनजाति समाज के संदर्भ में यह असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, संपत्ति पर अधिकार तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यद्यपि जनजातीय समाज को परंपरागत रूप से अपेक्षाकृत समानतावादी माना जाता है, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर महिलाओं को अनेक सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह असमानता समय के साथ सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा एवं नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव से परिवर्तित भी होती है, जिससे इसके अध्ययन के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है।

### 2. प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांत

लैंगिक असमानता को समझने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। नारीवादी सिद्धांत (Feminism) यह प्रतिपादित करता है कि पितृसत्तात्मक संरचनाएँ महिलाओं के शोषण और असमानता का मूल कारण हैं तथा समान अधिकारों और अवसरों की आवश्यकता पर बल देता है। संघर्ष सिद्धांत (Conflict Theory) के अनुसार समाज में संसाधनों और शक्ति का असमान वितरण विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है, जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं की स्थिति को कमजोर बनाता है। अंतर्विभाजन (Intersectionality) का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि लैंगिक असमानता केवल लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि जाति, वर्ग, जनजातीय पहचान, क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक कारकों के साथ मिलकर



# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

कार्य करती है। जनजातीय महिलाओं के संदर्भ में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बहुस्तरीय वंचनाओं का अनुभव करती हैं।

### 3. वैचारिक मॉडल

इस अध्ययन का वैचारिक मॉडल यह दर्शाता है कि लैंगिक असमानता एक स्वतंत्र चर नहीं, बल्कि विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के अंतर्संबंध का परिणाम है। सामाजिक कारकों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक मान्यताएँ, पारिवारिक संरचना) और आर्थिक कारकों (जैसे रोजगार, आय, संपत्ति पर अधिकार, गरीबी) को स्वतंत्र चर (Independent Variables) के रूप में माना गया है, जबकि महिलाओं की स्थिति—जैसे निर्णय-निर्माण में भागीदारी, सामाजिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वतंत्रता—को आश्रित चर (Dependent Variable) के रूप में देखा गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी नीतियाँ, शिक्षा का प्रसार, शहरीकरण एवं जागरूकता को मध्यस्थ (Intervening Variables) के रूप में शामिल किया गया है, जो इन संबंधों को प्रभावित करते हैं। यह मॉडल दर्शाता है कि इन सभी कारकों के पारस्परिक प्रभाव से लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं उसमें होने वाले परिवर्तन को समझा जा सकता है।

### परिणाम एवं चर्चा

**सारणी 1:** जिला बड़वानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की सामाजिक स्थिति का सांख्यिकी विश्लेषण

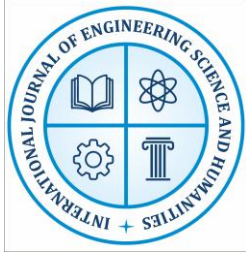
क्र	विवरण	संख्या	माध्य	माध्य विचलन	माध्य मानक त्रुटि	माध्य मानक विचलन	टी-मूल्य
1	शहरी क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुष	100	52.4	8.1	1.02	10.2	2.87
2	ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुष	100	48.1	8.7	1.10	11.0	

स्वतंत्रता की कोटि (df) = 198

पी-मूल्य  $\approx 0.005$

0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक

बड़वानी जिला के संदर्भ में प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। शहरी पुरुषों का माध्य (52.4) ग्रामीण पुरुषों (48.1) से अधिक है, जो उनके अपेक्षाकृत बेहतर सामाजिक स्तर को दर्शाता है। दोनों समूहों में माध्य विचलन लगभग समान है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में विविधता अधिक देखी गई है। t-



# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

मूल्य (2.87) तथा p-मूल्य ( $\approx 0.005$ ) यह संकेत करते हैं कि यह अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है ( $p < 0.05$ )। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है। निष्कर्षतः, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, संसाधनों एवं अवसरों की अधिक उपलब्धता सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित सुविधाएँ सामाजिक स्तर को प्रभावित करती हैं।

**सारणी 2:** जिला बड़वानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का सांख्यिकी विश्लेषण

क्र	विवरण	संख्या	माध्य	माध्य विचलन	माध्य मानक त्रुटि	माध्य मानक विचलन	टी-मूल्य
1	शहरी क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति की महिलाएं	100	50.6	7.9	0.99	9.9	2.41
2	ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति की महिलाएं	100	47.2	8.5	1.07	10.7	

स्वतंत्रता की कोटि (df) = 198

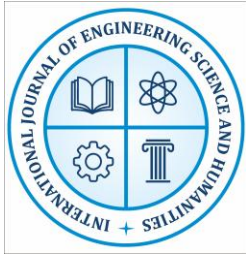
पी-मूल्य  $\approx 0.017$

0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक

बड़वानी जिला के संदर्भ में प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। शहरी महिलाओं का माध्य (50.6) ग्रामीण महिलाओं (47.2) की तुलना में अधिक है, जो उनकी अपेक्षाकृत बेहतर सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। माध्य विचलन लगभग समान होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में अधिक विविधता देखी गई है। t-मूल्य (2.41) एवं p-मूल्य ( $\approx 0.017$ ) यह सिद्ध करते हैं कि यह अंतर 0.05 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है। निष्कर्षतः, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, जागरूकता एवं रोजगार अवसरों की अधिक उपलब्धता महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और पारंपरिक संरचनाएँ उनकी स्थिति को सीमित करती हैं।

**सारणी 3:** जिला बड़वानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति का सांख्यिकी विश्लेषण

क्र	विवरण	संख्या	माध्य	माध्य विचलन	माध्य मानक	माध्य मानक	टी-मूल्य



# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

					त्रुटि	विचलन	
1	शहरी क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाएं	200	51.5	8.0	0.71	10.0	3.69
2	शहरी क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाएं	200	47.7	8.6	0.76	10.8	

स्वतंत्रता की कोटि (df) = 398

पी-मूल्य  $\approx 0.0003$

0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक

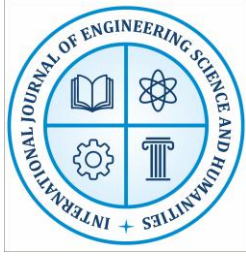
बड़वानी जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों के बीच महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। शहरी क्षेत्र का माध्य (51.5) ग्रामीण क्षेत्र (47.7) से अधिक है, जो यह दर्शाता है कि शहरी परिवेश में सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। माध्य विचलन (8.0 एवं 8.6) से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में विविधता अधिक है। माध्य मानक त्रुटि कम होने से आंकड़ों की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। t-मूल्य (3.69) तथा p-मूल्य ( $\approx 0.0003$ ) यह प्रमाणित करते हैं कि यह अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यंत सार्थक है ( $p < 0.05$ )। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है। निष्कर्षतः, शहरी क्षेत्रों में संसाधनों, शिक्षा एवं अवसरों की उपलब्धता सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है।

**सारणी 4:** जिला बड़वानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की आर्थिक स्थिति का सांख्यिकी विश्लेषण

क्र	विवरण	संख्या	माध्य	माध्य विचलन	माध्य मानक त्रुटि	माध्य मानक विचलन	टी-मूल्य
1	शहरी क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुष	100	55.2	9.0	1.12	11.2	3.62
2	ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुषों	100	49.3	9.6	1.20	12.0	

स्वतंत्रता की कोटि (df) = 198

पी-मूल्य  $\approx 0.0004$



# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक

बड़वानी जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की आर्थिक स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों के बीच उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। शहरी क्षेत्र के पुरुषों का माध्य (55.2) ग्रामीण क्षेत्र (49.3) से अधिक है, जो उनकी अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। माध्य विचलन (9.0 एवं 9.6) से यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में अधिक विविधता विद्यमान है। माध्य मानक त्रुटि के निम्न मान दोनों नमूनों की विश्वसनीयता को प्रमाणित करते हैं। t-मूल्य (3.62) एवं p-मूल्य ( $\approx 0.0004$ ) यह दर्शाते हैं कि यह अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यंत सार्थक है ( $p < 0.05$ ), अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है। निष्कर्षतः, शहरी क्षेत्रों में रोजगार, आय के विविध स्रोत एवं संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित अवसर आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

**सारणी 5:** जिला बड़वानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति का सांख्यिकी विश्लेषण

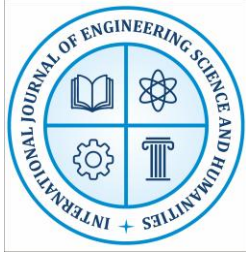
क्र	विवरण	संख्या	माध्य	माध्य विचलन	माध्य मानक त्रुटि	माध्य मानक विचलन	टी-मूल्य
1	शहरी क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति की महिलाएं	100	53.1	8.8	1.10	11.0	3.20
2	ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति की महिलाएं	100	48.0	9.3	1.16	11.6	

स्वतंत्रता की कोटि (df) = 198

पी-मूल्य  $\approx 0.0016$

0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक

बड़वानी जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों के बीच महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। शहरी क्षेत्र की महिलाओं का माध्य (53.1) ग्रामीण महिलाओं (48.0) की तुलना में अधिक है, जो उनकी अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। माध्य विचलन (8.8 एवं 9.3) यह संकेत देता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में अधिक विविधता पाई जाती है। माध्य मानक त्रुटि के मान दोनों नमूनों की विश्वसनीयता को पुष्ट करते हैं। t-मूल्य (3.20) तथा p-मूल्य ( $\approx 0.0016$ ) यह दर्शाते हैं कि यह अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यंत सार्थक है ( $p < 0.05$ ), अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है। निष्कर्षतः, शहरी क्षेत्रों में रोजगार



# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

अवसर, आय स्रोत एवं संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित अवसर उनकी आर्थिक प्रगति को प्रभावित करते हैं।

**सारणी 6:** जिला बड़वानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं आर्थिक स्थिति का सांख्यिकी विश्लेषण

क्र	विवरण	संख्या	माध्य	माध्य विचलन	माध्य मानक त्रुटि	माध्य मानक विचलन	टी-मूल्य
1	शहरी क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाएं	200	54.2	8.9	0.79	11.1	4.39
2	शहरी क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाएं	200	48.6	9.4	0.83	11.8	

स्वतंत्रता की कोटि (df) = 398

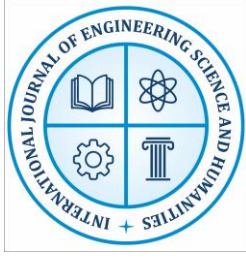
पी-मूल्य  $\approx 0.00001$

0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक

बड़वानी जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं की संयुक्त आर्थिक स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। शहरी क्षेत्र का माध्य (54.2) ग्रामीण क्षेत्र (48.6) से स्पष्ट रूप से अधिक है, जो यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ है। माध्य विचलन (8.9 एवं 9.4) से यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विविधता अधिक है। माध्य मानक त्रुटि के निम्न मान दोनों नमूनों की विश्वसनीयता को प्रमाणित करते हैं। t-मूल्य (4.39) तथा p-मूल्य ( $\approx 0.00001$ ) यह दर्शाते हैं कि यह अंतर अत्यंत उच्च स्तर पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है ( $p < 0.05$ ), अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है। निष्कर्षतः, शहरी क्षेत्रों में संसाधनों, रोजगार अवसरों एवं आय के विविध स्रोतों की उपलब्धता आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है।

## निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति समाज, विशेषकर बड़वानी जिला में लैंगिक असमानता एक बहुआयामी एवं संरचनात्मक समस्या के रूप में विद्यमान है, जो सामाजिक एवं आर्थिक दोनों कारकों से गहराई से प्रभावित होती है। अनुभवजन्य आंकड़ों के विश्लेषण से यह प्रमाणित हुआ कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है, जहाँ शहरी क्षेत्रों में निवासित पुरुषों एवं महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ है। इसके विपरीत,



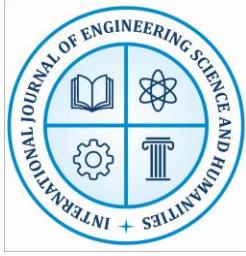
# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, सीमित रोजगार अवसर, पारंपरिक मान्यताएँ एवं शिक्षा का निम्न स्तर लैंगिक असमानता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोणों एवं साहित्य समीक्षा से यह भी स्पष्ट हुआ कि लैंगिक असमानता केवल व्यक्तिगत या सांस्कृतिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं, शक्ति संबंधों तथा संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम है। हालांकि, शिक्षा के प्रसार, सरकारी योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं सामाजिक जागरूकता के कारण महिलाओं की स्थिति में कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, फिर भी यह परिवर्तन अभी सीमित एवं असमान है। अतः यह आवश्यक है कि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल तथा स्थानीय संदर्भों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण किया जाए। समग्र एवं समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर ही जनजातीय समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है तथा सतत एवं संतुलित सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

## सन्दर्भ

1. कुमार, अजय (2019). आदिवासी महिलाओं पर सामाजिक असमानताओं का प्रभाव. पटना: बिहार विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 70-84।
2. खान, शफीक (2019). आदिवासी महिलाओं की स्थिति और उनके सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन. रांची: झारखंड विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 130-145।
3. गुप्ता, अंजलि (2018). आदिवासी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का संरक्षण. दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 125-138।
4. गुप्ता, मीना (2020). आदिवासी महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता. जयपुर विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 56-70।
5. चौरसिया, शालिनी (2019). आदिवासी समाज में लैंगिक असमानता: समस्याएँ और समाधान. रायपुर: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 112-125।
6. तिवारी, अमिता (2019). आदिवासी क्षेत्रों में लैंगिक समानता के प्रति सरकारी प्रयास. लखनऊ: अवध विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 84-97।
7. पाटिल, विनीता (2019). आदिवासी महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों की स्थिति. पुणे: महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 22-35।
8. पाठक, मुकेश (2020). आदिवासी क्षेत्र में लैंगिक असमानता: प्रभाव और समाधान. भोपाल विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 34-45।
9. वर्मा, नंदिनी (2020). आदिवासी समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति. रायपुर विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 89-101।
10. शर्मा, कुमारी अंजली (2020). आदिवासी महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास की चुनौतियाँ और समाधान. ग्वालियर विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 98-111।



# International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open-access journal  
Impact Factor 8.3 [www.ijesh.com](http://www.ijesh.com) ISSN: 2250-3552

11. शर्मा, रवि कुमार (2019). आदिवासी महिलाओं के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक. दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 45-59।
12. शेख, राशिद (2018). आदिवासी महिलाओं पर सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव: एक आलोचनात्मक अध्ययन. मुंबई: टाटा संस्थान, पृष्ठ संख्या 90-104।
13. शेख, रिया (2019). आदिवासी महिलाओं के अधिकार और विकास में बाधाएँ. जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 78-90।
14. सिंह, नरेश कुमार (2018). आदिवासी महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता: एक मूल्यांकन. पटना: बिहार विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 140-155।
15. सिंह, रवींद्र (2020). आदिवासी समुदायों में लैंगिक असमानता के सामाजिक-आर्थिक पहलू. दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 112-125।
16. सिंह, रश्मि (2019). आदिवासी महिलाओं के लिए विकास नीतियाँ और उनकी प्रभावशीलता. भोपाल: भोपाल विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या 100-112।